



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

सिक्किम में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व का एक अध्ययन

Jamuna Devi

Research Scholar, Department of Political Science, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University

Dr. Manoj Kumar Chaudhary

Professor, Department of Political Science, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University

सार

सिक्किम में, देश के दूसरे हिस्सों की तरह, पॉलिटिक्स में महिलाएं कुछ हद तक एक विरोधाभास दिखाती हैं। दूसरी जगहों की तरह, लगभग आधी आबादी वाली महिलाओं के पास सरकार के अलग-अलग लेवल पर चुने जाने वाले और चुने जाने वाले, दोनों तरह के पॉलिटिकल ऑफिस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। इससे यह सवाल उठता है कि सिक्किम में सरकार के सभी लेवल पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम क्यों है। यह चैप्टर इस सवाल के कई संभावित जवाब देने की कोशिश है और सिक्किम में महिलाओं की पॉलिटिकल हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व में लगातार बदलाव और निरंतरता के अलग-अलग पहलुओं को देखता है। यह सिक्किम में सरकार के राज्य और लोकल, दोनों लेवल पर महिलाओं की पॉलिटिकल हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा करता है। इस स्टडी में, पॉलिटिकल हिस्सेदारी शब्द का इस्तेमाल छोटे मतलब में वोटिंग और चुनावों में पार्टी कैंडिडेट के तौर पर हिस्सेदारी जैसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए किया गया है। प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल सरकार के अलग-अलग लेवल पर प्रतिनिधित्व के ज़रिए हिस्सेदारी के रूप के लिए किया गया

मुख्य शब्द - सिक्किम में महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल हिस्सेदारी

परिचय

पॉलिटिकल बराबरी लेकतंत्र की थ्योरीज़ का सेंटर है। यह तर्क दिया जाता है कि दुनिया की आधी आबादी महिलाएं बराबर की नागरिक हैं और इसलिए उन्हें पब्लिक डिजीजन-मेकिंग में पुरुषों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकतंत्र को एक आइडियल के तौर पर पेश किया जाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसलिए, आइडियल लेकतंत्र का मतलब है जेंडर, क्लास, काबिलियत, कल्चर वगैरह के बावजूद डिजीजन-मेकिंग प्रोसेस में सभी नागरिकों की सबको साथ लेकर चलने वाली भागीदारी और प्रतिनिधित्व। इसमें डिजीजन-मेकिंग पर कंट्रोल के इस्तेमाल में नागरिकों के बीच बराबरी शामिल है। एक ग्रुप के तौर पर महिलाओं ने हाल के दशकों में बहुत ज़्यादा वोटिंग पावर हासिल की है, लेकिन साथ ही उन्हें पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व और भागीदारी के मामले में हक से वंचित रखा गया है।

1975 तक राजशाही के तहत सिक्किम में गवर्निंग बॉडीज़ में लोगों की भागीदारी के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। कई ऐसी लिमिटेशन थीं जो लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस में फ्री भागीदारी से रोकती थीं। 1975 में सिक्किम राज्य में राजशाही का खत्म होना और लेकतंत्र की स्थापना हिस्टोरिक थी क्योंकि इसने डिजीजन-मेकिंग बॉडीज़ में लोगों की फ्री भागीदारी का रास्ता बनाया। सिक्किम में एक वैकल्पिक पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर लिबरल लेकतंत्र का उदय 1940 के दशक की शुरुआत के डेमोक्रेटिक आंदोलनों से जुड़ा है, जिसने बाद में पार्टी सिस्टम, जिम्मेदार सरकार, लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट और



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

यूनिवर्सल एडल्ट सफ़रेज (यासीन और छेत्री 2012; सिन्हा 1975) जैसे इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया। डेमोक्रेटिक राज्य असल में पॉलिटिकल प्रोसेस में प्रतिनिधित्व, लोगों की सहमति, विरोध और राज्य की पॉलिसी में मांगों के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर निर्भर करते हैं (यासीन और छेत्री 2012)। सिक्किम में डेमोक्रेटिक आंदोलन की प्रक्रिया में बदलाव की एक एक्टिव ताकत के तौर पर महिलाओं की मौजूदगी को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। 1940 के दशक से जब सिक्किम में वैकल्पिक पॉलिटिकल मॉडल की मांग के लिए पॉलिटिकल पार्टियां तेज़ी से बढ़ रही थीं, दूसरी ओर महिलाओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जब रूथ कार्थक लेपचानी ने 1966 में सिक्किम इंडिपेंडेंट फ्रंट नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। हालांकि, महिलाओं का पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व 1974 में ही शुरू हुआ जब हेमलता छेत्री लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली महिला मेंबर बनीं।

सिक्किम का डेमोग्राफिक प्रोफ़ाइल

हिमालय का एक राज्य सिक्किम 1975 में भारतीय गणराज्य का बाईसवां राज्य बना। सिक्किम का पहाड़ी राज्य $27^{\circ} 00' 46''$ से $28^{\circ} 07' 48''$ उत्तरी अक्षांश और $88^{\circ} 00' 58''$ से $88^{\circ} 55' 25''$ पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल एरिया 7096 है। सिक्किम एक खास पहाड़ी राज्य है जिसकी तीन-चौथाई सीमा पर इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, इसलिए इसका पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक महत्व है। उत्तर और उत्तर-पूर्व में इसकी सीमा तिब्बती पठार के बड़े हिस्सों, पूर्व में तिब्बत और भूटान की चुम्बी घाटी, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, सिक्किम की कुल आबादी 610,577 है, जिसमें 323,070 (53 प्रतिशत) पुरुष हैं जबकि 287,507 (47 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। राज्य की कुल आबादी में से 74.85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है जबकि 25.15 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में रहती है।

पार्टिसिपेशन और प्रतिनिधित्व

सिक्किम ज़िंदगी के सोशल और इकोनॉमिक पहलुओं के मामले में जेंडर पैरिटी की दिशा में काफी तरक्की कर रहा है। हालाँकि, दूसरी जगहों की तरह पार्टिसिपेशन और प्रतिनिधित्व एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मोटे तौर पर, महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उनका शामिल होना शामिल है, जिसमें वोटिंग, कैंडिडेट बनना, कैंपेनिंग, पॉलिटिकल ऑफिस में कब्ज़ा करना और अकेले या ग्रुप मेंबरशिप के ज़रिए लॉबिंग करना शामिल है। हालाँकि महिलाओं ने वोटिंग, कैंपेनिंग और पॉलिटिकल मीटिंग जैसे पार्टिसिपेशन के कुछ एरिया में अपनी मौजूदगी मज़बूत की है, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व के मामले में उन्हें हक से वंचित किया गया है। इस स्थिति ने लेकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौकों की गैर-बराबरी है। समाज के सभी नागरिकों को पॉलिसी डिस्कशन में हिस्सा लेने और प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलता है और कई लोग खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं (IDEA] 2013)। राज्य की आधी आबादी महिलाएँ हैं, जो सरकार के अलग-अलग लेवल पर अपॉइंटिव और इलेक्टिव, दोनों तरह के पॉलिटिकल ऑफिस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा संभालती हैं।

पार्टिसिपेशन और प्रतिनिधित्व लेकतंत्र के दो बुनियादी एलिमेंट और प्रिंसिपल हैं (प्फ़, 2013)। लेकतंत्र को एक आदर्श के तौर पर पेश किया जाता है, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। इसलिए, आदर्श लेकतंत्र का मतलब है सभी नागरिकों की जेंडर, क्लास, काबिलियत, कल्चर वगैरह के बावजूद फैसले लेने की



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

प्रक्रिया में सबको साथ लेकर चलने वाली भागीदारी और प्रतिनिधित्व। इसमें फैसले लेने पर कंट्रोल रखने में नागरिकों के बीच बराबरी शामिल है। पार्लियामेंट के वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि की है कि “लेकतंत्र की कामयाबी के लिए समाज के कामों को चलाने में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सच्ची पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, जिसमें वे बराबरी से काम करते हैं और एक-दूसरे को पूरा करते हुए, अपने मतभेदों से फायदा उठाते हैं” (IPUJ 2000)। ट्रेम्बली (2007) इसी तरह का दावा करते हैं कि पॉलिटिकल बराबरी की वैल्यू लेकतंत्र की थ्योरीज़ के लिए सेंट्रल है: यह तर्क दिया जाता है कि महिलाएं बराबर नागरिक हैं और इसलिए, फैसले लेने की प्रक्रिया में पुरुषों के साथ बराबर हिस्सा लेती हैं – नहीं तो, एक ‘डेमोक्रेटिक कमी’ होती है। इस तरह, प्रतिनिधित्व की बहस मुख्य रूप से दुनिया भर में नेशनल लेजिस्लेचर में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर फोकस करती हैं।

सिक्किम में, दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह, फैसले लेने वाली बॉडीज़ में महिलाओं के डिस्ट्रिक्टिव प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी एक बड़ी चिंता बन जाती है। शहरी और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए पचास परसेंट सीटें रिजर्व करना इस दिशा में एक बड़ी कोशिश रही है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं लोकल बॉडीज़ में जाती हैं, जो सरकार के लेवल पर सबसे निचला लेवल का पॉलिटिकल ऑफिस है। हालांकि, लोकल लेवल पर सरकार की कोशिशों के बावजूद, राज्य विधानसभा में इतने सालों के लेकतंत्र के बाद भी ग्रोथ उथल-पुथल वाली बनी हुई है। चुनी हुई महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी को समझाने वाला बढ़ता हुआ लिटरेचर बताता है कि बदलाव अपने आप नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टियों जैसे एक्टर्स की तरफ से सोच-समझकर की गई कोशिशें, जिनका खास मकसद ज़्यादा महिलाओं को पॉलिटिकल ऑफिस में चुनना होता है, इसके पीछे एक ज़रूरी वजह है। कई दूसरे लोग (जैसे डुवर्गर, 1955) इस बात पर सोचते हैं कि चुनी हुई महिलाओं की संख्या के लिए इलेक्टोरल सिस्टम का टाइप मायने रखता है।

सिक्किम में महिलाओं की स्थिति

सोशियो और इकोनॉमिक फैक्टर्स महिलाओं को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने में मदद करते हैं या रोकते हैं। छिब्बर (2002) लिखते हैं, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं की सोशियो-इकोनॉमिक रिसोर्स तक अलग-अलग पहुँच होती है और क्योंकि सोशियो-इकोनॉमिक स्थिति पॉलिटिकल भागीदारी पर असर डालती है, इसलिए महिलाएँ पुरुषों की तुलना में पॉलिटिकल रूप से कम एक्टिव होती हैं। इसी तरह, ग्लिसन (2001) का भी मानना है कि महिलाओं की पढ़ाई-लिखाई पुरुषों की तुलना में कम होती है और क्योंकि उनके वर्कफोर्स में होने की संभावना भी कम होती है, इसलिए महिलाएँ पुरुषों की तुलना में पॉलिटिकल रूप से कम एक्टिव हो सकती हैं। इसलिए, महिलाओं को सोशल और इकोनॉमिक रूप से और साथ ही पॉलिटिकल रूप से ऊपर उठाने के लिए सिक्किम ने अलग-अलग इंस्टीट्यूशनल उपाय शुरू किए हैं। महिलाओं के विकास के लिए अच्छी डेवलपमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इसलिए, राज्य की महिलाओं की स्थिति भारतीय संघ के कुछ दूसरे राज्यों की महिलाओं से बेहतर है (छेत्री और यासीन 2012)। देश के दूसरे हिस्सों के उलट, राज्य में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता और दहेज, सती और कन्या भ्रूण हत्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या काफी अच्छी है। पब्लिक लाइफ में महिलाओं की मौजूदगी साफ दिखती है और उन्होंने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल वगैरह कई तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लिया



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

है। राज्य में महिलाओं को मजबूत बनाने में सरकार के दखल से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है, जिसका असर पॉलिटिक्स में महिलाओं की पूरी हिस्सेदारी पर पड़ता है।

एजुकेशन

अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट बर्न्स, शोलज़मैन और वर्बा (2001) की स्टडी में पाया गया कि एजुकेशन 'पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक खास तौर पर पावरफुल प्रेडिक्टर' है। महिलाओं की आज़ादी को आगे बढ़ाने और समाज में उनकी जगह को बेहतर बनाने में एजुकेशन का अहम रोल है और महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर इसका ज़्यादा असर होता है। हालांकि, सिक्किम में 1975 से पहले एजुकेशन का सिस्टम सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए था। सिंह (1985) के मुताबिक, पुराने ज़माने के शासकों ने शायद सोचा होगा कि वे आम लोगों पर तभी तक राज कर सकते हैं जब तक वे अपनी प्रजा को अनपढ़ता, अज्ञानता और मासूमियत की खाई में डुबोए रखने में कामयाब रहेंगे। इसलिए, एजुकेशन सिर्फ़ अमीर तबके के बच्चों तक ही सीमित थी। हालांकि, सिदकियोगतुलकु ने सिक्किम में एजुकेशन को नया डायमेंशन दिया। उन्होंने 1909 में गंगटोक में एन्वे स्कूल, 1912 में नामची, रेनॉक और पाथिंग में सरकारी स्कूल जैसे कई स्कूल खोले और आम लोगों को अपने लड़के-लड़कियों को नए बने स्कूलों में भेजने के लिए बढ़ावा दिया (छेत्री सी., 2012)। उनके समय में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने लड़कियों का एक स्कूल खोला, लेकिन यह सिर्फ़ काज़ियों की बेटियों के लिए था और आम लोगों की लड़कियों को इस स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं थी (छेत्री सी., 2012)। इसलिए, राजशाही सिस्टम में शिक्षा का सिस्टम सिर्फ़ अमीर लोगों तक ही सीमित था, आम नागरिकों और महिलाओं को फॉर्मल शिक्षा तक कोई एक्सेस नहीं था।

स्रोत: भारत की जनगणना

सिक्किम में ज़िलेवार लिटरसी रेट (2011)

ज़िला	पुरुष	महिला	कुल
पश्चिम	84.86	72.12	78.69
दक्षिण	87.06	76.57	82.06
पूर्व	89.22	79.41	84.67
उत्तर	87.29	76.43	82.20
राज्य	87.29	76.43	82.20

सोर्स: छेत्री, 2019c

1975 से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार ने कई वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में स्कूल बनाना, एजुकेशन के लिए नेशनल प्रोग्राम जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नेशनल लिटरसी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और दूसरी नॉन-फॉर्मल एजुकेशन स्कीम को लागू करना। इन कोशिशों से आम तौर पर लिटरसी रेट और खासकर महिलाओं की लिटरसी रेट में काफी सुधार हुआ है (छेत्री और यासीन 2012)। फिगर 4.1 दिखाता है कि पिछले 30 सालों में महिलाओं की लिटरसी रेट में काफी सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार, सिक्किम की लिटरसी रेट 82.20 परसेंट तक पहुंच गई है, जो नेशनल रेट यानी 74.04 परसेंट से ज़्यादा है। पुरुषों की लिटरसी 87.29 परसेंट थी, जो



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

महिलाओं की रिकॉर्ड की गई 76.43 परसेंट लिटरैसी से ज़्यादा है। जेंडर गैप 10.86 परसेंट है। यह आंकड़ा दिखाता है कि 1951 में 1.2 परसेंट से 2011 में 76.43 परसेंट तक महिला लिटरैसी रेट में काफी सुधार हुआ है। दी गई 2011 में ज़िलेवार महिला लिटरैसी रेट से पता चलता है कि पूर्वी ज़िले में 79.41 परसेंट के साथ सबसे ज़्यादा लिटरैसी रेट दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी ज़िले में 72.12 परसेंट के साथ यह सभी ज़िलों में सबसे कम है।

महिलाओं की पॉलिटिकल हिस्सेदारी

सिक्किम 1975 में इंडियन यूनियन में मर्ज होने से पहले एक राजशाही राज्य था। नामग्याल वंश के तहत राजशाही 1642 से 1975 तक 333 साल तक चली। राजशाही शासन के दौरान, सिक्किम पर चोग्याल (राजा) द्वारा जारी शाही घोषणा के तहत राज किया जाता था। गवर्निंग बॉडीज़ में चुने हुए लोगों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रोविज़न नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से काज़ी और ठिकेदारों के हाथ में था। न केवल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि सिक्किम की ज़्यादातर आबादी भी इन सामंतों के अंडर थी। चोग्याल के अंडर सिक्किम राज्य में पहला चुनाव 1953 में हुआ था।

हालांकि, इलेक्टोरल सिस्टम में कई लिमिटेशन थीं जो पॉलिटिकल प्रोसेस में फ्री हिस्सेदारी से रोकती थीं (छेत्री, 2019क)। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक चुनावों में आम तौर पर मिलने वाले एक ज़रूरी एलिमेंट की कमी है। छेत्री (2019क) का तर्क है कि 'चोग्याल शासन के तहत चुनाव अनडेमोक्रेटिक और तानाशाही था क्योंकि यह बस ज़्यादातर आबादी को सरकार में हिस्सेदारी से बाहर रखता है। इसके अलावा, 30 साल से कम उम्र के लोगों को स्टेट काउंसिल की उम्मीदवारी नहीं दी गई, इस तरह बड़ी संख्या में लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। इसके अलावा, वोट देने वालों की उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और वे प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले होने चाहिए।

पॉलिटिकल पार्टियों के आने से लोगों को पॉलिटिकल हिस्सेदारी के मामले में एकजुट करने में मदद मिली। जैसे ही भारत 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ादी के विचारों ने सिक्किम के पढ़े-लिखे और समझदार लोगों को सामंतवाद की गुलामी से छुटकारा पाने और लेकतंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन, तीन पॉलिटिकल संगठन 'गंगटोक में प्रजा सुधारक समाज', टेमी तारकू में 'प्रजा सम्मेलन' और चाखुंग में 'प्रजा मंडल' बनाए गए। बाद में, 1947 में इन संगठनों का विलय हो गया और सिक्किम स्टेट कांग्रेस नाम की पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी, जिसका मकसद राजशाही को खत्म करना और सिक्किम में लेकतंत्र स्थापित करना था। पॉलिटिकल पार्टियों को डेमोक्रेटिक संस्थाओं की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। पॉलिटिकल महत्व के मुद्दों को उठाने के अलावा, सिक्किम स्टेट कांग्रेस ने कैंपेन और आंदोलनों के ज़रिए लोगों को शिक्षित करके बहुत अहम भूमिका निभाई। इसका नतीजा 1953 का रॉयल प्रोक्लेमेशन और सिक्किम स्टेट काउंसिल का गठन था। काउंसिल में एक प्रेसिडेंट, बारह चुने हुए और पांच नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। सिक्किम में पहला आम चुनाव 1953 में हुआ था। चुनाव में, सभी भूटिया-लेप्चा सीटों पर सिक्किम नेशनल पार्टी ने कब्ज़ा कर लिया, जबकि सभी नेपाली सीटों पर सिक्किम स्टेट कांग्रेस ने जीत हासिल की। फिर भी, इस चुनाव ने सिक्किम के लोगों के चुनावी अनुभव की शुरुआत की।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

सिक्किम में 1953–1974 तक राजनीतिक पार्टियों के चुनावी नतीजे						
राजनीतिक दल	1953	1958	1967	1970	1973	1974
सिक्किम राज्य कांग्रेस	6	8	2	4	2	.
सिक्किम राष्ट्रीय पार्टी	6	6	5	7	9	1
सिक्किम राष्ट्रीय कांग्रेस	.	.	8	5	5	.
सिक्किम कांग्रेस	.	.	.	.	.	31
निर्दलीय	.	.	3	2	2	.
कुल	12	14	18	18	18	32

स्रोत: छेत्री (2019d)

वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी

मर्जर के बाद के समय में डेमोक्रेटिक अनुभव महिलाओं के लिए सबको साथ लेकर चलने वाली भागीदारी वाली जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एकजुट या एक साथ कोशिशों का गवाह है। सिक्किम में महिलाओं ने मर्जर के बाद के समय में वोटर के तौर पर अपनी भागीदारी के क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। इसलिए, महिला वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है और अब लगभग पुरुषों के बराबर है। सिक्किम में विधानसभा चुनावों में वोटर के तौर पर महिलाओं की भागीदारी समय के साथ काफी बढ़ी है। साल 1979 में 65.71 प्रतिशत महिला वोटर टर्नआउट 2019 में 78.38 प्रतिशत तक पहुँच गया है (चित्र 4.3)। विधानसभा चुनाव 2019 में वोटर के तौर पर पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी लगभग बराबर दर्ज की गई, जहाँ पुरुष वोटर महिला वोटर्स से सिर्फ 0.48 प्रतिशत ज़्यादा थे। असल में, 2014 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर टर्नआउट प्रतिशत 81.31 था, जो पुरुषों के 80.31 प्रतिशत से ज़्यादा था। सिक्किम में विधानसभा चुनावों में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज, लोकसभा के आम चुनावों में महिलाओं के औसत वोटिंग परसेंटेज से बहुत ज़्यादा है। लोकसभा के आम चुनावों में महिलाओं के औसत वोटिंग टर्नआउट में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो 1962 में 46.6 परसेंट से बढ़कर साल 2019 में लगभग 67 परसेंट हो गया है। वोटिंग टर्नआउट में जेंडर गैप भी 1962 में 15.4 परसेंट से घटकर 2019 में 0.2 परसेंट हो गया है। 2019 के आम चुनाव में पुरुषों और महिलाओं का वोटर टर्नआउट लगभग बराबर है। असल में, 2019 के आम चुनाव में सभी चुनावों में महिलाओं का सबसे ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट हुआ था।

अलग-अलग आम चुनावों में वोटिंग का प्रतिशत (1951–2019)				
चुनाव का साल	महिला रजिस्टर्ड वोटर्स की तुलना में महिलाओं को मिले वोट (%)	पुरुष रजिस्टर्ड वोटर्स की तुलना में पुरुषों को मिले वोट (%)	वोटर टर्नआउट (%)	टर्नआउट में अंतर



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

1951	-	-	45.67	-
1957	-	-	47.74	-
1962	46.6	62	55.42	15.4
1967	55.5	66.7	61.33	11.2
1971	49.1	60.9	55.29	11.8
1977	54.9	65.6	60.49	10.9
1980	51.2	62.2	56.92	11.0
1984	59.2	68.4	64.01	9.2
1989	57.3	66.1	61.95	8.8
1991	50.6	61.6	55.88	11.0
1996	53.4	62.1	57.94	8.7
1998	57.7	65.7	61.97	8.0
1999	55.6	63.9	59.99	8.3
2004	53.6	62.2	57.98	8.6
2009	55.8	60.3	58.19	4.5
2014	65.5	67	66.44	1.5
2019	67.2	67	67.09	0.2

राज्य के हिसाब से, तीन नॉर्थ-ईस्ट राज्यों यानी त्रिपुरा (92.9p), नागालैंड (91.3p) और असम (90.38p) ने सभी राज्यों/नज़्मे में सबसे ज़्यादा महिला वोटर टर्नआउट दर्ज किया (Fig- 4.4)। नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में, सिक्किम असेंबली में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में पहले स्थान पर है; जहां तक महिलाओं के वोटर टर्नआउट का सवाल है, यह 6जी स्थान पर है। नागालैंड, जहां राज्य असेंबली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जीरो परसेंट है, चुनाव में महिलाओं के वोटिंग टर्नआउट का दूसरा सबसे ज़्यादा परसेंट है। इस तरह, सिक्किम समेत नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में वोटिंग में भाग लेने वाली महिलाओं का परसेंट काफी ज़्यादा है। हाल के चुनावी डेटा के अनुसार, सिक्किम में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज उन कुछ राज्यों से ज़्यादा है, जिनकी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ (77.3p), हरियाणा (71.1p), उत्तर प्रदेश (60.3p) और मध्य प्रदेश (70.1p)।

पॉलिटिकल पार्टियों में महिलाएं

वोटिंग के अलावा, चुनाव लड़ना पॉलिटिकल हिस्सेदारी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। पॉलिटिकल एलीट लोगों को भर्ती करने और चुनने का काम पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में होता है। कुनोविच और पैक्सटन (2005) का कहना है कि किसी व्यक्ति, पुरुष या महिला को पॉलिटिकल ऑफिस के लिए चुनाव लड़ने के लिए, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा चुना और सपोर्ट किया जाना चाहिए। असल में, पार्टी कैंडिडेट्स को चुनना पॉलिटिकल पार्टियों का सबसे ज़रूरी काम माना जाता है। इसी तरह, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (2013) ने भी बताया कि "लगभग सभी



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे कोई भी चुनावी सिस्टम हो, वोटर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां ही चुने हुए ऑफिस के असली गेटकीपर होती हैं। इसलिए, पॉलिटिकल पार्टियों का रोल ज़रूरी माना जाता है – चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने वाली महिलाओं की संख्या और पार्टी के अंदरूनी स्ट्रक्चर में महिला लीडर, दोनों ही मामलों में।

जहां तक सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टियों की भूमिका का सवाल है, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए उनके दावे सिर्फ दिखावटी हैं। डेटा से पता चलता है कि बहुत कम महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट मिलते हैं। 1979 के चुनावों में 11 महिला उम्मीदवारों में से सिर्फ चार पार्टी टिकट होल्डर थीं और बाकी इंडिपेंडेंट थीं। 1985 के चुनाव में भी ऐसा ही पैटर्न रहा, जहां चार महिलाओं को नेशनल पार्टियों से और दो को स्टेट पार्टियों से टिकट मिला, जबकि ज्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थीं। इन दो असंबली चुनावों में कोई भी महिला चुनी नहीं गई। हालांकि, 1989 में महिला उम्मीदवारों की संख्या घटकर चार रह गई। जिनमें से दो स्टेट पार्टियों से और दो नेशनल पार्टियों से थीं। स्टेट पार्टी की एक महिला चुनाव जीती। 1994 के असंबली चुनावों में, नौ महिलाएं चुनावी मैदान में थीं, जिनमें से चार महिला उम्मीदवारों को स्टेट पार्टियों से टिकट मिला, एक को नेशनल पार्टी से और बाकी चार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थीं। स्टेट पार्टी की एक महिला टिकट होल्डर चुनाव जीती। 1999 और 2004 में, महिला उम्मीदवारों की संख्या घटकर छह रह गई। महिला निर्दलीय उम्मीदवारों की अनुपस्थिति थी, जो पिछले चुनावों में नौ से घटकर 1999 और 2004 के विधानसभा चुनावों में छह होने का संभावित कारण हो सकता है। 2004 में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) एकमात्र राज्य पार्टी थी जिसने चुनाव में तीन महिला प्रतियोगियों को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में तीनों महिला राज्य पार्टी टिकट धारक निर्वाचित हुईं। 2009 के विधानसभा चुनाव में, महिला प्रतियोगियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। कुल में से, छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों द्वारा भरे गए थे, चार राज्य पार्टी से संबंधित थे, और अन्य तीन राष्ट्रीय पार्टी टिकट धारक थीं। शेष दो स्वतंत्र उम्मीदवार थे। एसडीएफ पार्टी द्वारा मैदान में उतारी गई सभी चार महिलाओं ने चुनाव जीता। इसके बाद के चुनावों में महिला प्रतियोगियों में मामूली गिरावट आई। 2014 में, 11 महिला प्रतियोगियों में से छह महिलाएं राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित थीं कुल 16 महिला उम्मीदवारों में से, चार महिलाएं SDF पार्टी की टिकट होल्डर थीं, दो SKM की थीं और तीन महिलाएं हमरो सिक्किम पार्टी (HSP) से थीं। बाकी पांच महिलाओं को नेशनल पार्टियों ने मैदान में उतारा था। इस चुनाव में, तीन महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गईं, जिनमें से दो SDF पार्टी की टिकट होल्डर हैं और एक ज़ड पार्टी से हैं।

विधानसभा चुनावों में पार्टी के अनुसार महिला उम्मीदवार (1979–2019)										
पार्टी का नाम	1979	1985	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019	Total
राज्य पार्टी										
सिक्किम कांग्रेस आर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
सिक्किम	-	1	1	3	1	-	-	-	-	6
संग्राम परिषद	-	-	1	-	-	-	-	-	-	



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

राइजिंग सन पार्टी	-	-	-	1	1	3	4	3	4	15
सिक्किम डेमोक्रेटिक	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
फ्रंट	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
सिक्किम क्रांतिकारी										
मोर्चा	-	3	2	1	4	1	2	3	4	20
सिक्किम प्रजातंत्र	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
कांग्रेस	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
नेशनल पार्टी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
इंडियन नेशनल	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
कांग्रेस										
जनता पार्टी	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
भारतीय जनता पार्टी	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
नेशनलिस्ट कांग्रेस	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
पार्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
ऑल इंडिया तृणमूल	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
कांग्रेस	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टी	7	5	-	4	-	-	2	1	-	19
सिक्किम हिमाली राज्य	11	11	4	9	6	6	15	11	16	86

सोर्स: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (1979–2014) के पास मौजूद डेटा के आधार पर कैलकुलेट किया गया। eci-gov-in

यह देखा गया है कि 1979 से 2019 तक, नेशनल पार्टियों की तरफ से सबसे ज़्यादा महिला कैंडिडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उतारे। स्टेट पार्टियों में से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सबसे ज़्यादा



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा। हैरानी की बात है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। यह देखते हुए कि कितनी महिला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाई, यह देखा गया है कि चुनावों में उनकी खुद की हिस्सेदारी कोई अच्छा ट्रेंड नहीं दिखाती है। यह इस बात का भी इशारा करता है कि पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को पार्टी कैंडिडेट बनाने में हिचकिचा रही हैं। एक इंडिपेंडेंट महिला कमजोर तरफ होती है क्योंकि यहां पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए काम करता है। अगर महिलाएं पॉलिटिकल ऑफिस में रहना चाहती हैं, तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टियों में अपने लिए जगह बनानी होगी। इसके अलावा, चुनाव जीतने वाली सभी महिला कैंडिडेट स्टेट पार्टियों से थीं। इसलिए, स्टेट असेंबली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्टेट पार्टियों द्वारा महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारना सही है। लेकिन, महिलाओं का पार्टी-वाइज़ एनालिसिस साफ़ दिखाता है कि पार्टियाँ महिलाओं को टिकट देने में शर्माती हैं।

आम चुनावों में महिला कैंडिडेट उतारते समय नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों का भी यही ट्रेंड रहा है। उदाहरण के लिए, नेशनल पार्टियों द्वारा महिला कैंडिडेट की संख्या 2009 में 137 से बढ़कर 2019 के चुनावों में 171 हो गई है। हालाँकि, महिला कैंडिडेट का पार्टी-वाइज़ एनालिसिस एक दशक में कोई खास बदलाव नहीं दिखाता है, न तो ठश्रच और न ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी काफी महिला कैंडिडेट उतार रही है। 2009 में सबसे ज़्यादा महिला कैंडिडेट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (Iपूज्) ने उतारे थे, जो Iपूज् के कुल कैंडिडेट का 18.5 परसेंट था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (छब्) 10.2 परसेंट महिला टिकट होल्डर के साथ दूसरे नंबर पर रही। भारतीय जनता पार्टी (ठश्रच) 10.1 परसेंट के साथ तीसरे और इंडियन नेशनल कांग्रेस (फूब) 9.7 परसेंट महिला कैंडिडेट के साथ चौथे नंबर पर रही। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी ऐसा ही पैटर्न जारी रहा, जिसमें पार्टियों द्वारा उतारे गए महिला कैंडिडेट के परसेंट में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। Iपूज् फिर से टॉप पर है, 37 परसेंट महिलाएं पार्टी टिकट होल्डर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सिस्ट (बूड) 14.4 परसेंट के साथ दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस और ठश्रच 12.8 परसेंट और 12.6 परसेंट के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। पार्टियों द्वारा मैदान में उतारी गई महिलाओं के परसेंटेज में फर्क है, सबसे ज़्यादा 37 और सबसे कम 2.9 परसेंट है, लेकिन सभी पार्टियां 33 परसेंट के बेंचमार्क से काफी कम महिलाओं को मैदान में उतार रही हैं।

2009 और 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा महिला उम्मीदवार						
पार्टी का नाम	2009			2019		
	कुल उम्मीदवारों की संख्या	महिला उम्मीदवारों की संख्या	कुल उम्मीदवारों के प्रतिशत के रूप में महिलाएं	कुल उम्मीदवारों की संख्या	महिला उम्मीदवारों की संख्या	कुल उम्मीदवारों के प्रतिशत के रूप में महिलाएं
AITC	27	5	18.5	62	23	37
BJP	433	44	10.1	435	55	12.6
BSP	500	28	5.6	383	24	6.2



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

CPI	56	4	7.1	48	4	8.3
CPIM	82	6	7.3	69	10	14.4
INC	440	43	9.7	420	54	12.8
NCP	68	7	10.2	34	1	2.9
इंडिपेंडेंट	3831	207	5.4	3443	226	6.5

सोर्स: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (2009–2019) मबप.हवअ.पद पर मौजूद डेटा के आधार पर कैलकुलेट किया गया।

हाल ही में हुए 17वें लोकसभा चुनाव में, कुल 8026 में से 724 (9 प्रतिशत) महिला उम्मीदवार थीं। हैरानी की बात है कि उनमें से सिर्फ 24 प्रतिशत नेशनल पार्टी की टिकट होल्डर थीं बाकी 8 प्रतिशत स्टेट पार्टी की टिकट होल्डर थीं, जबकि 37 प्रतिशत महिला उम्मीदवार रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टियों से थीं और उनमें से 31 प्रतिशत इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थीं। नेशनल और स्टेट पार्टियां महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने में हिचकिचा रही हैं।

इसके अलावा, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी महिला विंग होती है, जिन्हें फैसेले लेने में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इनक्यूबेट किया जा सकता है। हालांकि, इन बॉडी में उनकी मेंबरशिप से फैसेले लेने वाली बॉडी में महिलाओं का असली प्रतिनिधित्व मुश्किल से ही होता है। किश्वर (1996) का कहना है कि सबसे अच्छी महिला सांसद भी पार्टी में खुद को अलग-थलग और बेबस महसूस करती हैं, क्योंकि कुछ महिला नेता चुनावी मुकाबले और पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा महिलाओं की एंट्री को आसान नहीं बना पाई हैं और इसलिए वे एक बेअसर माइनॉरिटी बनी हुई हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि शहरी लोकल गवर्नमेंट सिक्किम के लोगों के लिए नई है, लेकिन बहुत कम समय में इन लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में काफी सुधार हुआ है। सिक्किम म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007 के लागू होने के बाद लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दिखाता है। सिक्किम म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007 में 2009 में बदलाव किया गया था। म्युनिसिपैलिटी (अमेंडमेंट) एक्ट 2009 महिलाओं के पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व के मामले में ज़रूरी है क्योंकि इस खास एक्ट ने महिलाओं के लिए सीटों के रिज़र्वेशन का परसेंटेज 33 से बढ़ाकर 40 कर दिया है। 2010 के म्युनिसिपल इलेक्शन में कुल 47 सीटों में से 19 (40 परसेंट) महिला मेंबर चुनी गईं। म्युनिसिपैलिटी एक्ट में 2015 में और बदलाव किया गया। इस खास बदलाव ने रिज़र्वेशन का परसेंटेज 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया है। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटों के रिज़र्वेशन के परसेंटेज में बढ़ोतरी से ज़मीनी लेवल पर पॉलिटिक्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसलिए, 2015 में हुए म्युनिसिपल चुनाव में, कुल 53 सीटों में से 28 महिला सदस्य चुनी गईं, यानी 52 परसेंट। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का राजनीति में आना बिना रिज़र्वेशन सिस्टम के मुमकिन नहीं होता। सरकार की रिज़र्वेशन पॉलिसी और राजनीति में महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी ने महिलाओं को एक अहम खिलाड़ी बना दिया है। इससे महिलाओं के लिए पॉलिटिकल पावर तक पहुँचना और पॉलिसी के फैसेले लेने में असर डालना मुमकिन हो गया।

निष्कर्ष

वोटर के तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी, पार्टी में महिलाओं की हिस्सेदारी, मिनिस्ट्री में महिलाओं की हिस्सेदारी, लेजिस्लेचर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और लोकल बॉडीज़ में महिलाओं की हिस्सेदारी का



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

एनालिसिस महिलाओं की हिस्सेदारी का एक उलटा नज़रिया देता है। सबसे पहले, हाल ही में हुए 2019 के असेंबली चुनाव में महिला वोटों में हिस्सेदारी में 78.38 परसेंट की बढ़ोतरी अपने चरम पर पहुँच गई है। वोटिंग परसेंटेज लगभग 0.48 परसेंट के गैप के साथ जेंडर बराबरी पर पहुँच गया है। दूसरे बड़े एरिया जहाँ महिलाएँ बहुत अच्छा कर रही हैं, वे हैं लोकल बॉडीज़ में उनकी हिस्सेदारी। इसका कारण लोकल बॉडीज़ में रिज़र्वेशन के रूप में पॉज़िटिव भेदभाव के उपाय में मिलता है। यह प्रतिनिधित्व में जेंडर बराबरी लाने का एक असरदार तरीका साबित हुआ है। इसके उलट, ऊँचे लेवल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। असेंबली और कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है, असेंबली में 0 से 12 परसेंट और कैबिनेट में 0 से 16 परसेंट है।

महिलाओं की वोटिंग में हिस्सेदारी और लोकल बॉडीज़ में उनकी भागीदारी को देखते हुए, पॉज़िटिव भेदभाव का उपाय – लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन, समय की ज़रूरत लगता है और यह महिलाओं की हिस्सेदारी को रोकने वाली कई रुकावटों को दूर करने में बहुत मदद करेगा और इस तरह महिलाओं की पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व में सुधार करेगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियाँ सेंट्रल ऑर्गनाइज़ेशन हैं जिनके ज़रिए नागरिक चुनाव लड़ते हैं। महिलाओं की पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व में पॉज़िटिव बदलाव लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को लेजिस्लेचर में ज़्यादा महिलाओं को शामिल करने में प्रो-एक्टिव होना होगा।

ग्रंथ सूची

1. इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (2008). इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स: ए सर्वे ऑफ़ मेन एंड वीमेन इन पार्लियामेंट्स (नंबर 54)। स्विट्ज़रलैंड: PCL लॉज़ेन।
2. इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (2019). वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स। स्विट्ज़रलैंड: PCL लॉज़ेन
3. इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (2019). वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स। www-pchn.org@wmn&e@world&arc-htm से लिया गया। 22 अक्टूबर 2019 को एक्सेस किया गया।
4. इवानागा, कुजुकी (2008). इंट्रोडक्शन: एशिया में महिलाएं और पॉलिटिक्स: एक कम्पेरेटिव नज़रिया। काजुकी इवानगा (एडिटर) में, और एशिया में रिप्रेजेंटेशन: रुकावटें और चुनौतियाँ, (पेज 1–22)। डेनमार्क: NIAS प्रेस। कम्पेरेटिव पॉलिटिकल स्टडीज़, 42(1): 56–81.
5. जयाल, निरजा जी. (2005). लोकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना: डेमोक्रेटाइज़ेशन के लिए कोटा का असर, 13 (1): 15–35.
6. जयाल, एन. और नुसबाम, एम. (2003). जेंडर और गवर्नेंस: एक इंट्रोडक्शन।
7. ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली: UNDP-
8. जयाल, निरजा गोपाल (2006). लोकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना: डेमोक्रेटाइज़ेशन के लिए कोटा का असर, 13(1): 15–35.
9. कान, किम फ़िडकिन (1996). एक औरत होने के पॉलिटिकल नतीजे. न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस.



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

10. कलिता, जर्ना (2016). पॉलिटिक्स में औरतों का रिप्रेजेंटेशन: नेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत. द क्लेरियन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल, वॉल्यूम 5(2): 54–58.
11. कपूर, मुदित और रवि, शमिका (2014). इंडियन डेमोक्रेसी में औरतें वोटर: एक साइलेंट रेवोल्यूशन. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम XLIX, नंबर 12: 63–67.
12. कार्लेकर, हिरण्मय (1996). फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी बहुत कुछ करना है। इंडियन जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज़, 3 (2): 275–281.